भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 586

गुरूवार, 4 दिसम्बर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक)

तेलंगाना में युवाओं मे बेरोजगारी

586. श्री रविचंद्र वद्दीराजू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल की तिमाहियों में, तेलंगाना में युवा बेरोजगारी की उच्च दर दर्ज की गई है;

(ख) राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों और युवतियों में बेरोजगारी दर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के कारणों का आकलन किया है;

(घ) राज्य में युवतियों की श्रम शक्ति भागीदारी दर क्या है; और

(ङ) राज्य में रोजगार सृजन और कौशल विकास में सुधार के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, तेलंगाना में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 आयु वर्ग के युवाओं का अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 23.3% से घटकर वर्ष 2023-24 में 16.6% हो गई है। इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए तेलंगाना में बेरोजगारी दर निम्नानुसार हैः

बेरोजगारी दर (% में)			
श्रेणी	पुरूष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	12.0	17.2	13.8
शहरी	16.7	30.7	20.9
ग्रामीण + शहरी	13.9	22.1	16.6

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

इसके अतिरिक्त, 2017-18 और 2023-24 के दौरान तेलंगाना सहित देश में सामान्य स्थिति के आधार पर विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं का अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (% में)		
सामान्य शैक्षिक स्तर	**2017-18**	**2023-24**
साक्षर और प्राथमिक शिक्षा तक	8.3	2.6
पूर्व-माध्यमिक	13.7	4.2
माध्यमिक	14.4	4.9
उच्चतर माध्यमिक	21.1	8.8
माध्यमिक और उससे अधिक	25.4	15.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका दर्शाती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर में कमी आई है।

तेलंगाना में, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं के लिए अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2017-18 में 23.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 32.1% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार तेलंगाना सहित देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं (तेलंगाना सहित) को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए ' फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****